UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS

ONE STOP SOLUTION

By **Faiyaz Sir**

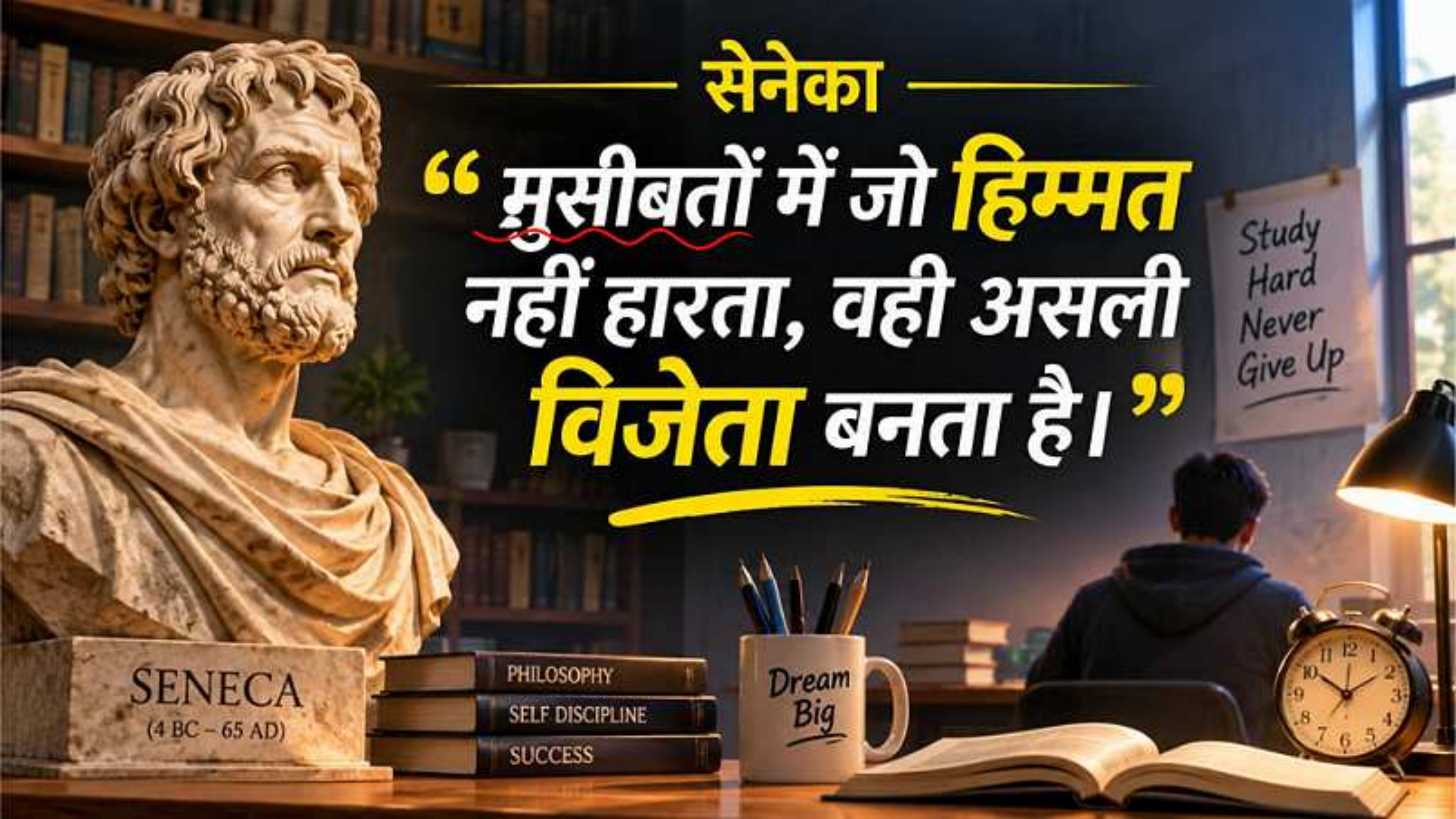


The Indian EXPRESS | THE HINDU | pib PRESS INFORMATION BUREAU

31 OCTOBER

COMPLETE COVERAGE | EXAM FOCUSED | ANALYSIS MADE EASY | STATIC + CURRENT INTEGRATION

STAY AHEAD
STAY PREPARED


सेनेका
“मुसीबतों में जो हिम्मत नहीं हारता, वही असली विजेता बनता है।”
Study Hard Never Give Up
SENECA
(4 BC – 65 AD)
PHILOSOPHY
SELF DISCIPLINE
SUCCESS
Dream Big

आज क्या पढ़ेंगे?

- MSP Rabi Crops
- PM-Kishan Scheme
- SIR – Form 7
- NSSB
- TN Relaxes Age Limit - Exam
- UPSC/SPSC – Removal of Chairman & Members
- NCR Air Pollution
- GSLV – F18/NVS03
- World Bank – Poverty & Equity Brief for India 2026
- Oil Imports
- US Military & AI
- India China
- Israel – War Crime
- G-20 Foreign Ministers Meeting
- Student Protest – France & Italy
- New York Ban on Social Media
- UCC in UP
- INS Tarkash
- Bharat YUVA Samvaad
- High Level Committee on Banking
- Namaste Scheme

Agriculture - Farmer's Welfare

रबी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य: मार्केटिंग सीजन 2027-28

मूल्य आश्वासन, खरीद और किसानों की पहुंच का सुदृढ़ीकरण

Posted On: 29 OCT 2026 11:10AM

*न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों को मूल्य आश्वासन प्रदान करने और कृषि नियोजन एवं निवेश संबंधी सूचित निर्णय लेने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है। 30 सितंबर 2026 को सरकार ने **रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2027-28** के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत 324 लाख मीट्रिक टन (एमटी) उपज के लिए किसानों को अनुमानित **₹90,962 करोड़** का भुगतान किया जाएगा। एमएसपी समर्थन के बढ़ते पैमाने का प्रतिबिंब बीते कुछ वर्ष में खरीद के रुझानों और भुगतानों में दिखाई देता है। छः रबी फसलों की खरीद 2004-05 से 2013-14 के दौरान 2,302 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़कर 2014-15 से 2025-26 के दौरान 3,921 एलएमटी हो गई। इसी के अनुरूप, **एमएसपी भुगतान** 22.65 लाख करोड़ से बढ़कर **28.36 लाख करोड़** हो गया। इस बीच, डिजिटल प्लेटफॉर्म खरीद और भुगतान प्रक्रियाओं की सुगमता और पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं। मूल्य आश्वासन, विस्तारित खरीद और प्रौद्योगिकी-सक्षम वितरण मिलकर किसानों की बाजारों तक पहुंच को मजबूत कर रहे हैं और कृषि संबंधी निर्णयों में अधिक भरोसे का समर्थन कर रहे हैं।*

न्यूनतम समर्थन मूल्य: मूल्य स्थिरता के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करना

- किसान की आर्थिक आय केवल कृषि उत्पादन से ही नहीं, बल्कि फसल की कीमत से भी निर्धारित होती है। महीनों की मेहनत, संसाधनों और निवेश को खेती में लगाने के बाद, आखिरकार बाजार मूल्य ही किसान की आमदनी और कृषि कार्यों को जारी रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए, बाजार मूल्यों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से कृषि आय में काफी अनिश्चितता आ सकती है और भविष्य की खेती से संबंधित निर्णयों पर भी असर पड़ सकता है।
- इस संदर्भ में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों को सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण नीतिगत साधन है। यह एक मूल्य आश्वासन तंत्र प्रदान करता है जिसके माध्यम से सरकार पूर्व निर्धारित कीमतों पर पात्र कृषि उत्पादों की खरीद करती है। एमएसपी किसानों को लाभकारी प्रतिफल सुनिश्चित करता है और साथ ही कृषि निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।
- मूल्य आश्वासन प्रदान कर, एमएसपी किसानों को बाजार में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। जब बाजार मूल्य कम होते हैं, तो एमएसपी पर खरीद योग्य उपज को घोषित मूल्य पर बेचने का एक अवसर प्रदान करती है। यह व्यवस्था कीमतों में अनिश्चितता को कम करने, कृषि आय की स्थिरता को बनाए रखने और आगामी कृषि मौसमों के लिए योजना बनाने में सहायक होती है। अपेक्षित प्रतिफल में विश्वास को मजबूत करके, एमएसपी किसानों को बेहतर बीजों, कृषि प्रौद्योगिकी और अन्य उत्पादकता बढ़ाने वाले इनपुट में निवेश करने के निर्णयों में भी योगदान देता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे निर्धारित होते हैं

- सरकार **22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)** की घोषणा करती है। ये एमएसपी **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी)** की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। इन सिफारिशों में संबंधित राज्य **सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों** के विचारों को ध्यान में रखा जाता है। इसके साथ ही, तोरिया और छिलका रहित नारियल के लिए एमएसपी क्रमशः रेपसीड, सरसों और खोपरा के लिए घोषित एमएसपी के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।



- विभिन्न फसलों के लिए **एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी कई कारकों** पर विचार करता है। इनमें शामिल हैं:
- उत्पादन लागत
- घरेलू और वैश्विक बाजारों में फसलों की मांग और आपूर्ति
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें
- फसलों के बीच कीमत में समानता
- कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें
- व्यापक अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव, और

उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन

- एमएसपी की गणना में इस्तेमाल किए गए उत्पादन लागत में किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम और मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, बीज, उर्वरक, खाद और सिंचाई पर किए गए खर्च शामिल हैं। इसमें पंप सेट चलाने के लिए प्रयुक्त डीजल और बिजली, कृषि उपकरणों और भवनों पर मूल्य को होने वाले नुकसान, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और अन्य विविध खर्च भी शामिल हैं। इसके साथ ही, कृषि गतिविधियों में लगे परिवार के सदस्यों के योगदान को मान्यता देने के लिए पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य भी शामिल किया जाता है। एमएसपी की गणना के लिए **सभी 22 अनिवार्य फसलों** और सभी राज्यों में एक समान लागत-अनुमान सूत्र लागू किया जाता है।

रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28						
क्रम संख्या	फसल	एमएसपी 2027-28 (₹/क्विंटल)	उत्पादन की लागत 2027-28 (₹/क्विंटल)	लागत पर मार्जिन (%)	एमएसपी 2026-27 (₹/क्विंटल)	एमएसपी में बढ़ोतरी (निश्चित)
1	गेहूं	2,610	1,264	106	2,585	25
2	जौ	2,286	1,447	58	2,150	136
3	चना	5,958	3,751	59	5,875	83
4	मसूर दाल	7,390	3,854	92	7,000	390
5	सरसों और सरसों	6,613	3,367	96	6,200	413
6	कुसुम	7,215	4,810	50	6,540	675

- कुसुम के लिए **एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी 675 रुपये प्रति क्विंटल** घोषित की गई है। इसके बाद **सरसों और रेपसीड के लिए 413 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल के लिए 390 रुपये प्रति क्विंटल** और **जौ के लिए 136 रुपये प्रति क्विंटल** की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं और चना के एमएसपी में भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी की गई है।
- उत्पादन लागत पर लाभ के मामले में, गेहूं का अनुमानित लाभ मार्जिन सबसे अधिक 106% है, इसके बाद सरसों और रेपसीड का 96%, मसूर दाल का 92% और चना का 59% है। रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2027-28 के दौरान, **324 लाख मीट्रिक टन (एमटी)** उपज के लिए किसानों को लगभग **90,962 करोड़ रुपये** का भुगतान किए जाने का अनुमान है। रबी फसलों के लिए बढ़े हुए एमएसपी का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

- सितंबर 2018 में शुरू की गई यह योजना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसका एक प्रमुख घटक **मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)** है। यह योजना तब सक्रिय होती है जब अधिसूचित दालों, तिलहनों और खोपरा के बाजार मूल्य कटाई के चरम समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाते हैं। **उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू)** मानकों को पूरा करने वाली पात्र उपज को **वैध भूमि अभिलेख रखने वाले पूर्व-पंजीकृत किसानों** से **एनएएफईडी** और **एनसीसीएफ** के माध्यम से सीधे खरीदा जाता है। इससे बिचौलियों का उन्मूलन होता है और किसानों को मजबूरी में उत्पाद बेचने से बचाया जा सकता है।

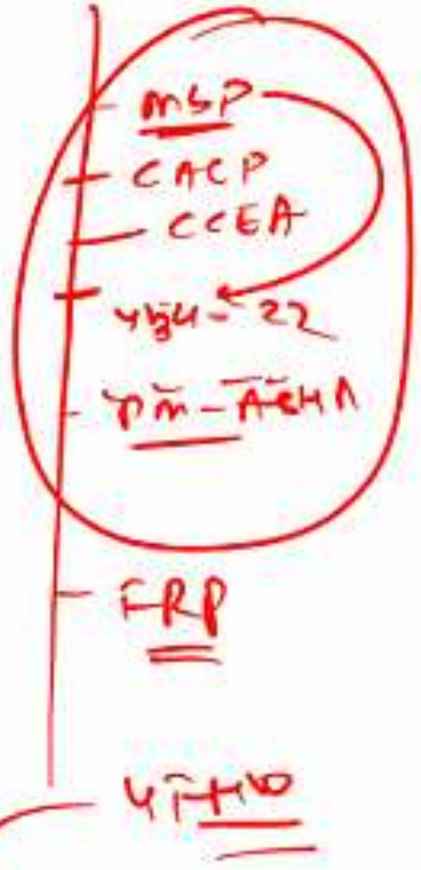
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Practice Questions)

प्रश्न 1: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) रबी और खरीफ सहित विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है।
2. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) देश में MSP की आधिकारिक घोषणा करती है।
3. MSP को वैधानिक बैकिंग (कानूनी गारंटी) प्राप्त है, जिसके तहत निजी खरीदार भी किसानों से MSP से कम कीमत पर फसल नहीं खरीद सकते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3



मुख्य परीक्षा (Mains Practice Question)

- **प्रश्न:** "न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली भारतीय कृषि और खाद्य सुरक्षा की रीढ़ रही है, किंतु इसके समक्ष कई संरचनात्मक और वित्तीय चुनौतियाँ भी मौजूद हैं।" इस कथन के आलोक में MSP व्यवस्था के लाभों का विश्लेषण करें तथा किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि विपणन में सुधार के लिए इसके समक्ष मौजूद वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा करें। *(उत्तर 250 शब्दों में लिखें)*

पत्र सूचना कार्यालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

Farmer's Welfare

PM-KISHAM

पीएम-किसान की 24वीं किस्त

9.34 करोड़ किसानों को 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

Posted On: 30 OCT 2026 3:57PM

*पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को **प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन किस्तों** में प्रदान की जाती है, जिससे **कृषि निवेश और घरेलू वित्तीय स्थिरता** को समर्थन मिलता है। इसकी 24वीं किस्त के अंतर्गत 9.34 करोड़ किसानों को 18,690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की गई, जिससे कुल संचयी वितरण **4.64 लाख करोड़ रुपये** से अधिक हो गया। आधार से जुड़े बैंक खाते, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई-केवाईसी और डिजिटल सत्यापन पारदर्शिता को मजबूत करते हैं तथा बिचौलियों की भूमिका को कम करते हैं। इस योजना को **वर्ष 2030-31** तक जारी रखने के लिए **3.15 लाख करोड़ रुपये** का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस योजना से किसानों की आय सुरक्षा के लिए निरंतर सहायता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।*

पीएम-किसान: किसानों की आय सुरक्षा को मजबूत बनाना

- सरकार ने 30 अक्टूबर 2026 को **गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)** की 24वीं किस्त जारी की। **9.34 करोड़** से अधिक पात्र किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में लगभग **18,690 करोड़ रुपये** प्राप्त हुए। यह राशि **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)** प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित की गई, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई। इस योजना को *'अन्नदाता सम्मान'* सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल माना जाता है।
- हाल ही में, जुलाई 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना को वर्ष **2026-27 से वर्ष 2030-31** तक जारी रखने को मंजूरी दी। इस अवधि के दौरान योजना के लिए कुल **3.15 लाख करोड़ रुपये** का वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है। यह मंजूरी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराती है कि किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि का आधार है।



पीएम-किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता

- पीएम-किसान एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है, जिसे **24 फरवरी, 2019** को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देशभर में कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवारों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र किसान परिवार को **प्रति वर्ष 6,000 रुपये** की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में उनके **आधार से जुड़े बैंक खातों** में जमा की जाती है।
- पीएम-किसान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता ने किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी और अन्य कृषि संबंधी आवश्यकताओं में **समय पर निवेश** करने में सक्षम बनाया है। इससे **किसानों की उत्पादक क्षमता में वृद्धि हुई है, अनौपचारिक ऋण पर उनकी निर्भरता कम हुई है** और **ग्रामीण परिवारों की वित्तीय स्थिरता मजबूत हुई है।**
- अब तक, देशभर के **पात्र किसान परिवारों को** 24 किस्तों के माध्यम से **4.64 लाख करोड़ रुपये** से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। भूमि अभिलेखों को पीएम-किसान पोर्टल पर जोड़े जाने के बाद ही किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, किसानों के लिए अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करना और ई-केवाईसी सत्यापन पूरा करना भी अनिवार्य है। किसानों की आय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, **केंद्रीय बजट 2026-27** में पीएम-किसान योजना के लिए **60,000 करोड़ रुपये** आवंटित किए गए हैं।

पीएम-किसान के तहत धनराशि अंतरण की प्रक्रिया

- यह प्रक्रिया पीएम-किसान पोर्टल, मोबाइल ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से **किसानों के पंजीकरण** से शुरू होती है। राज्य सरकारें **पात्रता का सत्यापन** करती हैं और लाभार्थियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इसके बाद, प्रणाली **आधार और बैंक खाते के विवरण का सत्यापन** करती है तथा अपात्र आवेदकों को छाँटकर अलग कर देती है। राज्य सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, **खाते के सत्यापन के लिए डेटा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)** को भेजा जाता है। पात्र अभिलेखों के आधार पर **धनराशि अंतरण के अनुरोध** और भुगतान आदेश तैयार किए जाते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग स्वीकृति आदेश जारी करता है। इसके बाद, प्रायोजक बैंकों और **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)** के माध्यम से **भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाती है।** अंततः, धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है, जिससे लाभों का त्वरित, पारदर्शी और कुशल वितरण सुनिश्चित होता है।



कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहायता प्रणाली: किसान-ईमित्र

- सितंबर 2023 में, सरकार ने किसान –ई मित्र की शुरुआत की। यह पीएम-किसान डिजिटल इकोसिस्टम के साथ एकीकृत ए आई आधारित चैटबॉट है। इसे **एकस्टेप फाउंडेशन** और **भाषिणी** के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है। यह चैटबॉट किसानों को कई भारतीय भाषाओं में **भुगतान, पंजीकरण और** योजना के अंतर्गत **पात्रता से संबंधित जानकारी वास्तविक समय** में प्रदान करता है।
- यह प्लेटफ़ॉर्म **11 प्रमुख भाषाओं** : हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, बांग्ला, ओड़िया, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मराठी और कन्नड़—में 24/7 सहायता प्रदान करता है। इससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले उपयोगकर्ताओं के लिए इस सेवा तक पहुँच आसान हो जाती है। **वॉयस – एंड टेक्स्ट- बेस्ड क्वेरी** के माध्यम से किसान अपने आवेदनों की स्थिति जाँच सकते हैं, भुगतान संबंधी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं और योजना से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims Practice Questions)

प्रश्न 1: 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)' योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक केंद्रीय सेक्टर की योजना (Central Sector Scheme) है जिसके तहत शत-प्रतिशत वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
2. इस योजना के तहत सभी भूमिधारक कृषक परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है।
3. इस योजना का वित्तपोषण राज्य सरकारों के सहयोग से 50:50 के अनुपात में किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains Practice Question)

- **प्रश्न:** "प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और डिजिटल गवर्नेंस ने कृषि क्षेत्र में लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को बदल दिया है।" प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के विशेष संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें तथा किसानों की वित्तीय सुरक्षा और कृषि निवेश में इसकी भूमिका का विश्लेषण करें। *(उत्तर 250 शब्दों में लिखें)*

महत्वपूर्ण तथ्य

SC seeks report from ECI on Form 7 misuse

- Election Commission says it did not accept any Form 7s filed in violation of the norms in U.P.
- Election body was responding to Congress MP's petition alleging widespread fraud during the SIR
- Court asks ECI to look into the issues raised, take the necessary action and file a compliance report

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The Election Commission of India (ECI) told the Supreme Court on Friday that though it found "false" Form 7s for deletion of voters during the Uttar Pradesh Special Intensive Revision (SIR), none of them were accepted.

Appearing before a Bench headed by Chief Justice of India Surya Kant, senior advocate Dama Seshadri Naidu, for the ECI, said corrective measures were taken promptly on discovery of such "false" forms. Authorities had rejected Form 7s filed in violation of norms, the ECI said.

The ECI was responding to allegations levelled in a petition filed by Congress leader and Barabanki MP Tanuj Punia, represented by senior advocate Subran Khurshid and advocate Shariq Ahmed, about widespread misuse and fraud in connection with bulk filing of Form 7 during the claims and objections phase of the Uttar Pradesh SIR.

Mr. Ahmed questioned the ECI's claim that false Form 7s were stopped at the gates. He said the court must subject this claim to judicial scrutiny. Counsel argued that it was exactly the lack of any corrective measures in the Uttar Pradesh SIR that "rendered denied" the filing of bulk Form 7s in Karnataka and Telangana.

"Of the 32 Form 7s in the Hata Assembly constituency in Uttar Pradesh, two were signed by the booth-level officer. All these forms pertained to deletion of voters belonging to one community," counsel submitted. The court asked Mr. Ahmed to submit a note with details and additional information, if any, on the issue.



"Let the ECI look into these issues, take necessary action and file a compliance report," the court observed.

The Uttar Pradesh SIR process ended in April. Over two crore voters were removed from the rolls.

Mr. Khurshid and Mr. Ahmed pointed out that the issue raised in the Barabanki MP's application needed to be taken up without any further delay as the process for State Assembly elections may commence as early as in December 2026 or early January next year.

Numerous applications

Mr. Punia's plea detailed that "numerous" Form 7 applications were generated and submitted with incomplete or false particulars of the objector, invalid identity details, forged signatures, and, in several instances, in the names of persons who had subsequently denied filing any such objections. It also alleged that booth-level officers (BLOs) received pre-filled Form 7 applications seeking deletion of multiple electors, including electors who had already been verified during the SIR process.

The Barabanki MP said these instances had raised "serious apprehensions regarding the integrity of the objection mechanism". He has sought initiation of penal action under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950, and other applicable provisions of law, against persons found to have made false declarations, filed fraudulent objections, impersonated objectors, or otherwise misused the Form 7 mechanism to procure wrongful deletions from the electoral rolls.

Mr. Naidu's submissions in the Supreme Court on Friday echo an affidavit filed by the ECI in September, in which it referred to multiple reports received from electoral officials on the ground about attempts to submit Form 7 in bulk to BLOs.

These included the instance in the Hata Assembly constituency, where a person only identified as "Yogendra" "insolvently" left on the table of the BLO Form 7s to delete 32 voters. The man, "Yogendra", remains untraceable.

Again, the ECI affidavit said a report from the Electoral Registration Officer of Ghaziabad narrated an attempt to submit 87s in bulk to the BLO. "However, owing to its bulk quantity, the forms were not accepted," the EC said. The poll body said the incident prompted it to "categorically direct" BLOs not to digitise any form without proper checking, and not to accept Form 7s in bulk.

The affidavit said media reports led to an inquiry in Sakaldiha, where officials unearthed false Form 7s, which were neither issued by the BLO concerned nor filed as per procedure.

Form 7s for deletion of voter names are obtained from the District Election Officers, Voter Registration Centres, BLOs or the voter service portal. An applicant has to submit Form 7, duly filled and signed, with EPIC and phone number, either personally to the BLO or online.

The affidavit said Form 7s were also found inside "envelopes at the residences of certain BLOs". "Upon due enquiry, the persons in whose names the Form 7s were purportedly filed, denied submitting them. They further stated that the Forms were false," the EC said.

- BNSS Section 163
- Article 19 (1)
- Article 19 (3)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- ECI
- CEC – EC's
- SIR
- RPA 1950 – 21(3)
- RPA 1950 – 28 (RER-1960 - 6,7,8)
- RPA 1951 - 29(A)
- Conduct of Election Rules 1961 – 4(A) – Form 26

महत्वपूर्ण तथ्य

Union Labour Ministry sets up social security Boards for unorganised, gig, platform workers

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Union Labour Ministry on Friday notified the constitution of the National Social Security Board for Unorganised Workers with 40 members, and the National Social Security Board for Gig & Platform Workers with 22 members.

Union Minister for Labour and Employment Mansukh Mandaviya is the chairman of both Boards, which have representatives from the Central and State governments, prominent aggregator companies, employers, civil society organisations, workers' unions, and associations representing gig and platform workers. Union Labour Secretary is the Vice-Chairman of the Boards.

Targeted welfare

The mandate of the Boards is to design, monitor and recommend targeted welfare schemes for gig and platform workers and traditional unorganised workers.

The Boards will meet at least thrice a year, and the Union government will prescribe rules of procedure for them.

The functions of the Boards include recommending suitable schemes for different sections of unorganised workers, gig workers and platform workers; advising the Union government on the administration of the Social Security Code; monitoring social welfare schemes for unorganised workers, gig workers and platform workers; reviewing the record-keeping functions performed at the State level; reviewing the expenditure from the fund and account; and undertaking other functions assigned to it by the Union government from time to time.



The Boards will design and monitor schemes for workers.

The Labour Department officers of NDA-ruled Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Andhra Pradesh, and Gujarat are members of the Boards.

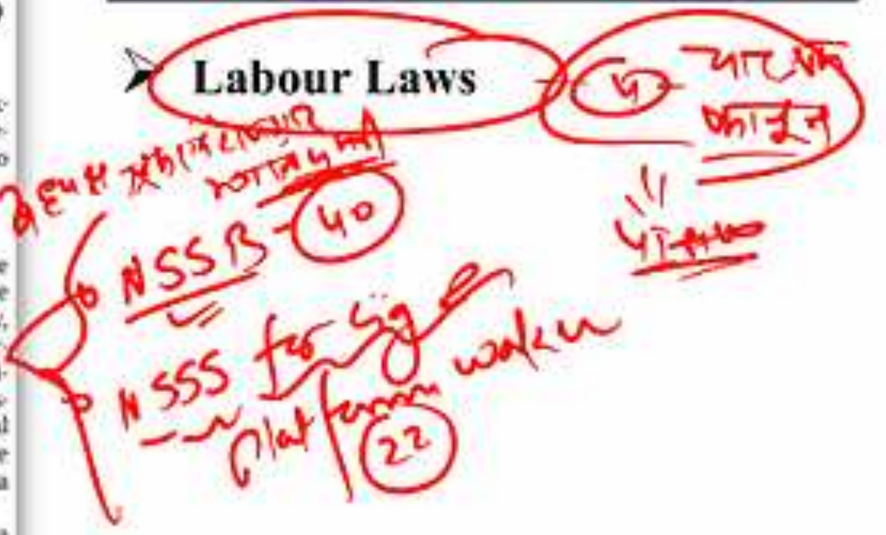
Representatives of Bharatiya Mazdoor Sangh, Laghu Udyog Bharati, aggregator companies such as Eternal Group (formerly known as Zomato Ltd.), Swiggy Ltd., Zepto Ltd., Urban Company and Rapido, Indian Federation of App-Based Transport Workers, V.V. Giri National Labour Institute and Dattopant Thengadi Board for Workers Education and Development are also members.

'Historic shift'

"Established under the statutory framework of the Code on Social Security, these Boards mark a historic shift by integrating digital gig and platform professionals into India's formal welfare architecture," the Labour Ministry said in a statement.

However, All India Trade Union Congress general secretary Amarjeet Kaur said the constitution of the boards is heavily tilted towards the Union Government, and it is filled with pro-BJP unions and employers' organisations.

YouTube Homework



महत्वपूर्ण तथ्य

1. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (NSSB) क्या है?

- राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (National Social Security Board - NSSB) **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)** के तहत गठित एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है।
- **मुख्य उद्देश्य:** असंघाटित क्षेत्र (Unorganised Sector) के श्रमिकों, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करना और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- **अध्यक्षता:** केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (Union Minister for Labour and Employment) बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।
- **संरचना:** इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, एग्रीगेटर कंपनियों (जैसे Swiggy, Zomato, Ola, Uber आदि के प्रतिनिधि), नियोक्ता, ट्रेड यूनियनों और गिग/प्लेटफॉर्म वर्कर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

2. गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों (Gig & Platform Workers) के लिए NSSB की भूमिका

- पारंपरिक रोजगार में भविष्य निधि (PF), ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ मिलते हैं, लेकिन गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक (जैसे ऐप-आधारित डिलीवरी बॉय, कैब चालक, फ्रीलांसर) इससे वंचित रहते हैं।
- NSSB के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं:
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ (Social Security Schemes):** NSSB केंद्र सरकार को गिग/प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा (पेंशन) तथा विकलांगता कवर जैसी योजनाओं की सिफारिश करता है।
- **सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund - Section 114):** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत एक समर्पित 'सामाजिक सुरक्षा कोष' की स्थापना का प्रावधान है।
- **एग्रीगेटर्स का योगदान (Funding Mechanics):** डिजिटल एग्रीगेटर्स (जैसे Uber, Swiggy आदि) को अपने वार्षिक टर्नओवर का **1% से 2%** तक (जो श्रमिकों को दिए जाने वाले कुल भुगतान के 5% से अधिक न हो) इस कोष में जमा करना अनिवार्य है।
- **सार्वभौमिक पंजीकरण (Universal Registration):** सभी गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का ऑनलाइन पंजीकरण (जैसे e-Shram पोर्टल के माध्यम से) आधार से जोड़कर किया जाता है ताकि योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके।

महत्वपूर्ण तथ्य

Tamil Nadu relaxes age limit for joining State govt. services

N. Sai Charan
CHENNAI

The Tamil Nadu government on Friday enhanced the upper age limit for direct recruitment to various categories of government services by five years in an order issued by Chief Minister C. Joseph Vijay. An official release said the relaxation follows demands from candidates appearing for competitive examinations. It will be in addition to the age concessions available to candidates of the Backward Classes, the Backward Classes Muslims, the Most Backward Classes and Denotified Communities, the Scheduled Castes, the Scheduled Caste Arunthathiyar, the Scheduled Tribes, and destitute widows, it said.



C. Joseph Vijay

For Group I posts, the upper age limit for candidates in the general category has been raised from 32 to 37 years. For candidates belonging to the BC, BCM, MBC/DNC, SC, SCA, and ST categories and destitute widows, it has been increased from 37 to 42 years.

For persons with disabilities in the general category, the upper age limit for Group I posts has been raised from 42 to 47 years. For persons with disabilities belonging to the BC, BCM, MBC/DNC, SC, SCA, and ST categories and destitute widows, it has been increased from 47 to 52 years.

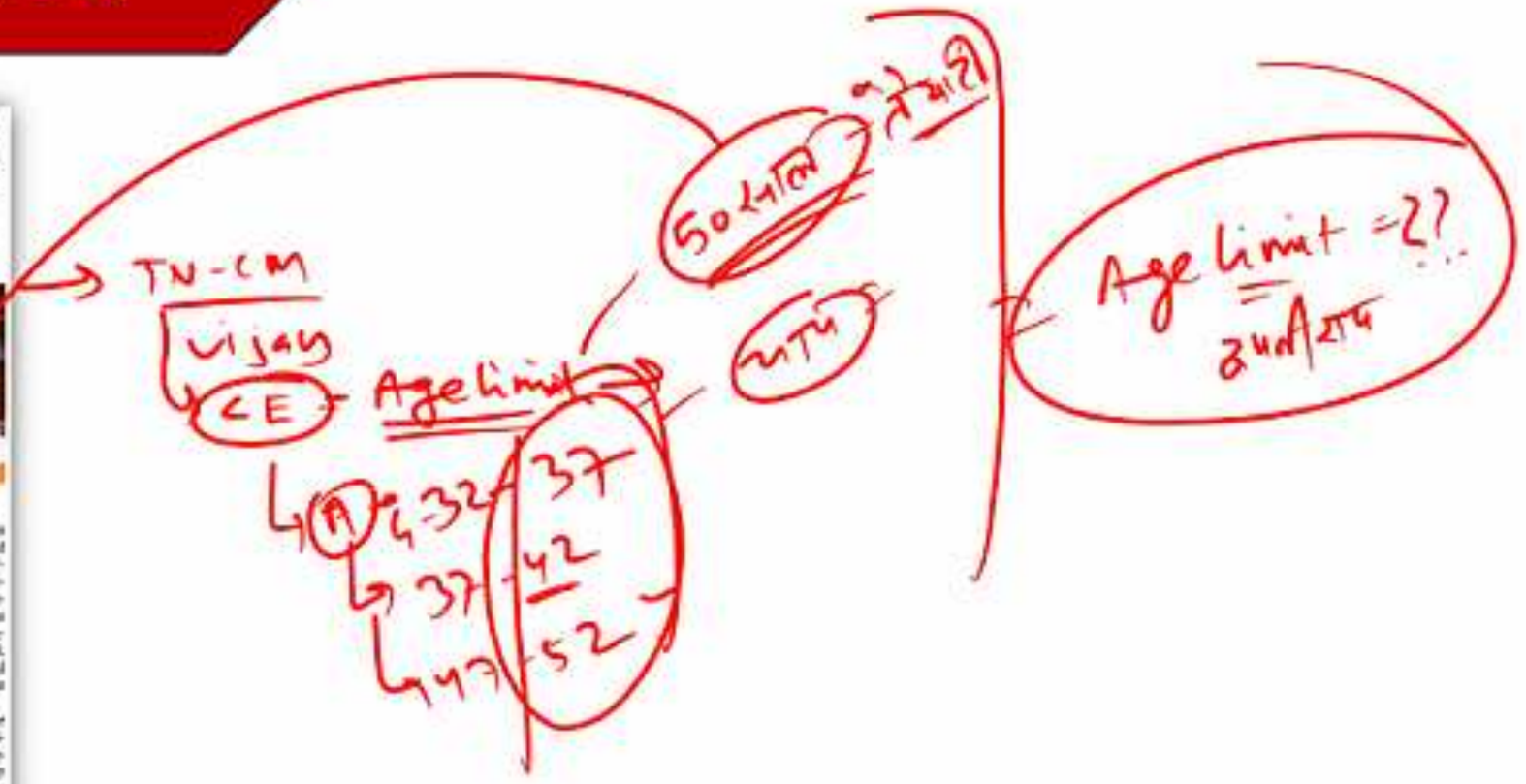
For Group II and IIA posts, the upper age limit has been raised from 30 to 35 years for candidates in the general category and from 40 to 45 years for persons with disabilities belonging to the general category. There is no upper age limit for candidates belonging to the BC, BCM, MBC/DNC, SC, SCA, and ST categories and destitute widows.

For Group IV posts, the upper age limit for candidates with higher qualification in the general category has been raised from 30 to 35 years and for persons with disabilities belonging to the general category, it has been raised from 40 to 45 years. There is no upper age limit for candidates with higher qualification belonging to the BC, BCM, MBC/DNC, SC, SCA, and ST categories and destitute widows.

For five years

The relaxation came into effect on Friday and would remain in force for five years.

The government said the decision would benefit thousands of candidates approaching the existing upper age limit for competitive examinations.



महत्वपूर्ण तथ्य

Deliberate manipulation in Kerala PSC exam, say police

The State Crime Branch alleged that the irregularities in the KPSC exam were carried out with the knowledge of officials, including a former KPSC Deputy Secretary and an Additional Secretary

The Hindu Bureau
THIRUVANANTHAPURAM

A remand report filed by the Kerala Police Crime Branch has alleged deliberate manipulation in the Kerala Public Service Commission (KPSC) examination conducted for the State Planning Board.

Such allegations have been detailed in the remand report of P. Satheesh, a former Deputy Secretary of the KPSC, who was arrested in connection with the case.

According to the report, the irregularities were purportedly carried out with the knowledge of officials, including Mr. Satheesh and another officer, R. Hari, an Additional Secretary, who is absconding.



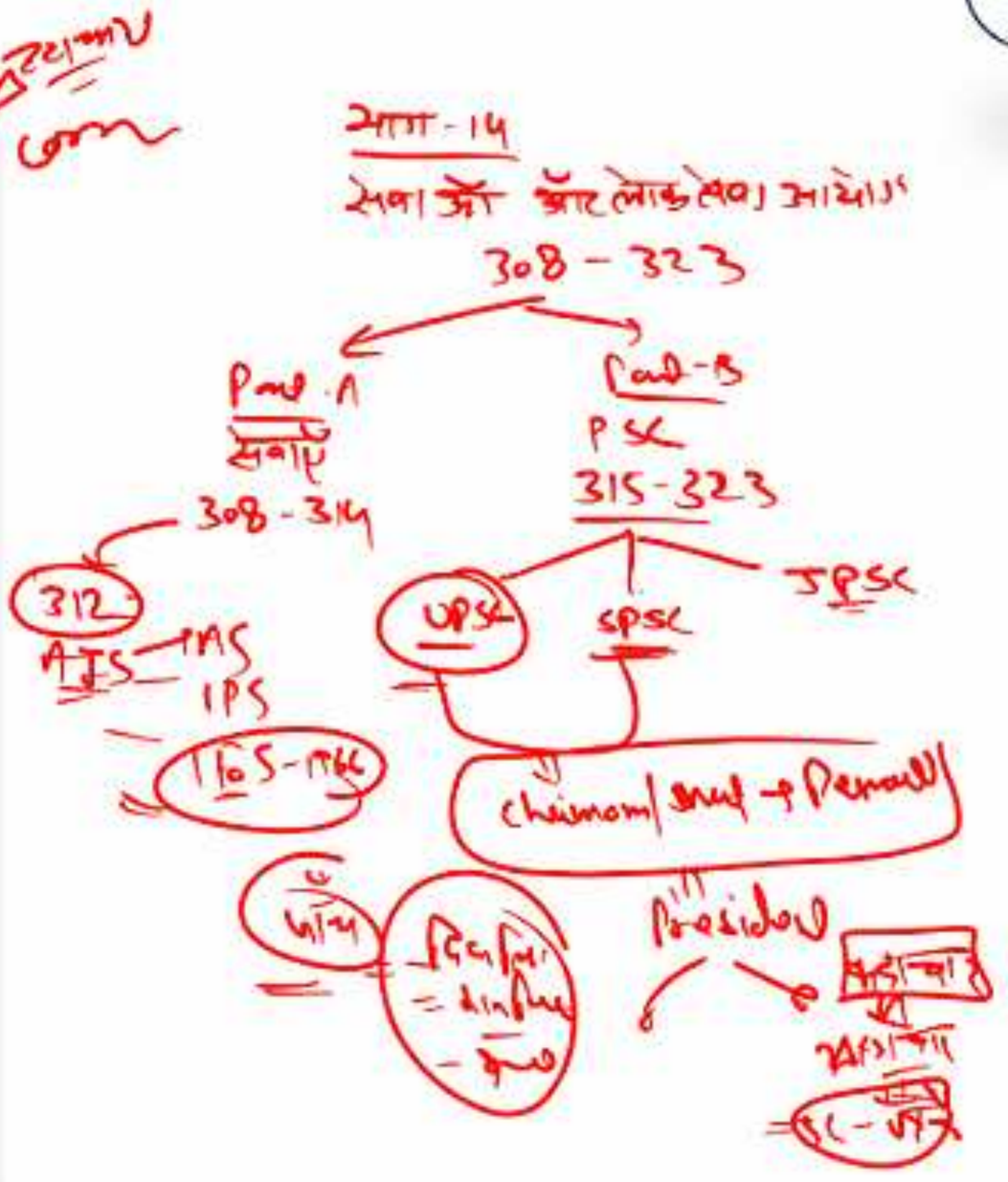
The SIT has issued notice to KPSC secretary to appear for questioning, plans to question 10 more members. FILE PHOTO

The police allege that 10 questions were intentionally excluded from the evaluation and that the online evaluation camp was closed without restoring those questions. The investigators suspect that the questions were deliberately withheld because their evaluation could have changed the ranking of candidates and prevented certain favoured persons from securing appointments.

Meanwhile, the Special Investigation Team (SIT) has issued notice to KPSC Secretary Saju George to appear for questioning on Saturday. The Controller of Examinations will also be summoned to seek clarification on the alleged involvement of KPSC Chairperson M.R. Baiju and the accused officials in the case.

Notices will be issued to 10 KPSC members directing them to appear for questioning. The investigation team has sought to clarify alleged inconsistencies in the statements given by Mr. Baiju during questioning a few days ago.

He reportedly maintained that the commission had not committed any errors in the Planning Board examination and that the irregularities resulted from technical errors committed by officials.



महत्वपूर्ण तथ्य

लोक सेवा आयोग (UPSC और State PCS) के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना

- UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) और State PCS (राज्य लोक सेवा आयोग) के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने का तरीका एक ही है। इन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। State PCS के सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है।
- भारतीय संविधान के भाग XIV (Part 14) में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के गठन, शक्तियों और कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

अनुच्छेद 315 से 323 तक का संपूर्ण विवरण

- **अनुच्छेद 315 – संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग:**
- केंद्र के लिए एक UPSC और प्रत्येक राज्य के लिए एक State PCS होगा। दो या दो से अधिक राज्य चाहें तो संसद के कानून द्वारा एक 'संयुक्त लोक सेवा आयोग' (JSPSC) भी बना सकते हैं।
- **अनुच्छेद 316 – सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल:**
- UPSC के सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद पर रहते हैं। State PCS के सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। UPSC के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति और State PCS की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं।
- **अनुच्छेद 317 – लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना:**
- UPSC और State PCS दोनों के ही अध्यक्ष या सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार, दिवालिया होने, या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। दुर्व्यवहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जाँच अनिवार्य है।
- **अनुच्छेद 318 – आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति:**
- UPSC के लिए नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास और State PCS के लिए राज्य के राज्यपाल के पास होती है। कार्यकाल के दौरान इन शर्तों में कोई भी हानिकारक बदलाव नहीं किया जा सकता।
- **अनुच्छेद 319 – आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध (रोक):**
- यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी अन्य लाभ के पद या रोजगार को न अपनाएं, ताकि उनकी निष्पक्षता बनी रहे।
- **अनुच्छेद 320 – लोक सेवा आयोगों के कार्य:**
- इसमें आयोगों के कर्तव्यों का वर्णन है, जैसे- सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं का संचालन करना और अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह देना।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **अनुच्छेद 321 – लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति:**
- संसद (UPSC के लिए) या राज्य का विधानमंडल (State PCS के लिए) कानून बनाकर लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र या कार्यों का विस्तार कर सकते हैं।
- **अनुच्छेद 322 – लोक सेवा आयोगों के व्यय (खर्च):**
- UPSC का पूरा खर्च (सैलरी, पेंशन आदि) भारत की संचित निधि पर भारित होता है और State PCS का खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। इस पर संसद या विधानसभा में मतदान नहीं होता।
- **अनुच्छेद 323 – लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन (Reports):**
- UPSC अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं। State PCS अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सामने रखवाते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

Govt. orders construction curbs, 50% work from home in Delhi-NCR from November 5

Restrictions timed to mitigate pollution load from burning of firecrackers, crop residue, says Union Minister; ban to apply on public infrastructure works; projects related to Railways, metro services, airports, hospitals, water supply and sanitation, national security and defence stand exempted

Nikhil M Babu
NEW DELHI

Union Environment Minister Bhupender Yadav on Friday announced a ban on construction and demolition activities in Delhi and the National Capital Region (NCR) from November 5 to 20, with exemptions for projects of national importance.

"This is the peak time [for air pollution], and the CAQM has conducted a scientific study on this. The ban will apply to dust generating demolition and outdoor civil construction activities," Mr. Yadav said.



Temporary measures: A worker goes on an anti-smog gun sprays water to curb air pollution in central Delhi. ANI

The Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM) issued an order on Friday night, directing the governments in Delhi-NCR to enforce the restrictions.

Projects related to the Railways, metro services, airports, inter-State bus terminals, hospitals, water supply and sanitation, national security and defence have been exempted, the order stated.

The prohibition will also apply to public infrastructure projects such as highways, roads, flyovers, overbridges, electricity transmission lines, pipelines and telecommunication projects, it added.

The CAQM also directed the Delhi government and authorities in five high vehicle-density districts — Gurugram, Faridabad, Sonipat, Ghaziabad and Gautam Buddha Nagar — to ensure that government and private offices operate with no more than 50% of their staff attending physically, while the remaining employees work from home during the same period. The order exempted industrial establishments and essential services where such an arrangement is not feasible.

Festive season curbs

A senior official told *The Hindu* that the measures were being taken in view of Deepavali on November 8, when firecracker emissions are expected to add to the pollution load.

"Stubble burning emissions are also expected to peak around the same time, with paddy harvesting under way," the official added.

In June, the Delhi government issued a ban on dust-generating demolition and construction activities from November 1 to January 31. During the day, Mr. Yadav also visited a newly developed Integrated Command and Control Centre (ICCC) at the CAQM headquarters to monitor measures to curb air pollution.

"The ICCC is a single-window digital centre that integrates various data streams. It also integrates data from 111 CAAQMS [continuous ambient air quality monitoring stations] operational in Delhi-NCR, over 2,300 industries, more than 3,200 active construction sites and traffic congestion hotspots," an official statement from the Minister's office read.

YouTube Homework

Air Pollution
↳ pm 2.5
↳ pm 10
↳ NCAP

महत्वपूर्ण तथ्य

1. GRAP (ग्रैप) – Graded Response Action Plan (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान)

- यह दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर के आधार पर लागू की जाने वाली आपातकालीन पाबंदियों और कदमों की एक चरणबद्ध कार्ययोजना है। हवा की गुणवत्ता (AQI) जैसे-जैसे खराब होती है, इसके अलग-अलग चरण (Stages) लागू किए जाते हैं:
- स्टेज 1 (खराब हवा - AQI 201 से 300): निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, सड़कों की सफाई और तंदूर में कोयले/लकड़ी पर रोक।
- स्टेज 2 (बहुत खराब हवा - AQI 301 से 400): डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध और पार्किंग शुल्क बढ़ाना ताकि लोग गाड़ियों का कम प्रयोग करें।
- स्टेज 3 (गंभीर हवा - AQI 401 से 450): आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी निर्माण और तोड़फोड़ (Construction & Demolition) के कामों पर पूरी रोक, और बीएस-III पेट्रोल व बीएस-IV डीजल गाड़ियों पर पाबंदी।
- स्टेज 4 (अत्यंत गंभीर हवा - AQI 450 से अधिक): दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक (जरूरी सामानों को छोड़कर), वर्क फ्रॉम होम और स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाना।

2. CAQM – Commission for Air Quality Management (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग)

- यह केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली वैधानिक आयोग (Statutory Body) है। इसका मुख्य काम दिल्ली और उसके आस-पास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण की निगरानी करना, नीतियां बनाना और विभिन्न राज्यों (जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी) के बीच तालमेल बिठाना है। GRAP को कब और किस चरण में लागू या हटाना है, इसका फैसला CAQM की सब-कमेटी ही लेती है।

3. AQMS – Air Quality Monitoring System (वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली)

- यह जमीन पर लगे उन वैज्ञानिक स्टेशनों और सेंसरों का नेटवर्क है जो हवा में मौजूद प्रदूषक कणों (जैसे PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि) को वास्तविक समय (Real-time) में मापते हैं। दिल्ली-एनसीआर में इसे व्यापक रूप से CAAQMS कहा जाता है। इसी सिस्टम से मिलने वाले डेटा से तय होता है कि आज दिल्ली की हवा का स्तर क्या है।

महत्वपूर्ण तथ्य

4. CAAQMS – Continuous Ambient Air Quality Monitoring System

- यह ज़मीन पर काम करने वाला प्रदूषण मापने का एक ऑटोमैटिक डिजिटल स्टेशन है।
- यह क्या करता है?: यह स्टेशन दिल्ली-एनसीआर की खुली हवा में 24 घंटे लगातार (Continuous) प्रदूषक कणों को मापता है। यह मुख्य रूप से PM2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जैसी जहरीली गैसों की मात्रा की जांच करता है।
- डेटा की पारदर्शिता: इसमें किसी इंसान का जाकर सैंपल लेने की जरूरत नहीं होती। यह ऑटोमैटिक तरीके से हर मिनट का लाइव डेटा सीधे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर पर भेजता रहता है। इसी डेटा के आधार पर आपके फोन में AQI (Air Quality Index) दिखाई देता है।
- नेटवर्क: वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में 111 से ज्यादा CAAQMS स्टेशन एक्टिव हैं, जो हर इलाके की हवा का सटीक हाल बताते हैं।

5. ICCC – Integrated Command and Control Centre

- अगर CAAQMS प्रदूषण पर नजर रखने वाली 'आंखें' हैं, तो ICCC इस व्यवस्था का 'दिमाग' (वार रूम) है।
- यह क्या करता है?: यह एक हाई-टेक, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम होता है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और आधुनिक डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में CAQM ने दिल्ली-एनसीआर के लिए PAVAN-ICCC (Platform for Air Quality Vigilance and Analytics for NCR) लॉन्च किया है।
- एक जगह सारा डेटा (Single-Window): यह सेंटर एक ही स्क्रीन पर कई अलग-अलग जगहों का डेटा एक साथ जोड़ता है (जैसे 111 CAAQMS स्टेशनों का डेटा, 3,200 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स के लाइव कैमरे, सैटेलाइट से पराली जलने की तस्वीरें, और ट्रैफिक जाम के हॉटस्पॉट्स)।
- तुरंत एक्शन (Real-time Action): जैसे ही किसी इलाके का CAAQMS स्टेशन यह दिखाता है कि वहां अचानक प्रदूषण बढ़ गया है, ICCC में बैठे अधिकारी तुरंत AI कैमरों और GPS की मदद से वजह का पता लगाते हैं (जैसे कूड़ा जलना या कंस्ट्रक्शन डस्ट) और संबंधित विभाग के नोडल अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेज देते हैं। इससे प्रदूषण पर मिनटों में एक्शन लिया जा सकता है।

दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं? (एक उदाहरण)

- मान लीजिए आनंद विहार इलाके में लगे CAAQMS स्टेशन ने रिपोर्ट किया कि वहां PM2.5 का स्तर अचानक खतरनाक रूप से बढ़ गया है। यह डेटा तुरंत ICCC (कंट्रोल रूम) की स्क्रीन पर फ्लैश होगा। ICCC के अधिकारी उस इलाके के लाइव कैमरों को चेक करेंगे। अगर वहां किसी साइट पर धूल उड़ती हुई दिखती है, तो तुरंत उस साइट को बंद करने या चालान काटने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

GSLV places next-generation navigation satellite into orbit

The NVS-03, with a mission life of 12 years, is expected to restore the functioning of the NavIC constellation; satellite carries an indigenous atomic clock, along with procured atomic clocks

Hemanth C.S.
BENGALURU

The Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV F15) late on Friday successfully launched the NVS-03 satellite from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, according to the ISRO.

The GSLV-F15 with the NVS-03 aboard lifted off from the second launch pad of the spaceport and 18 minutes later placed the satellite into the intended geosynchronous transfer orbit.

The 2,250 kg NVS-03 is the third satellite in the next generation navigation satellite system envisaged for providing continuity of navigation services for the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) series or the Navigation with Indian Constellation (NavIC). According to the ISRO, the satellite carries an indigenous atomic clock, along with procured atomic clocks.

"It also includes L1 signal in addition to existing L5/S signals with coverage over India land mass and a region extending 1,500 km around Indian geopolitical boundary," the ISRO said.

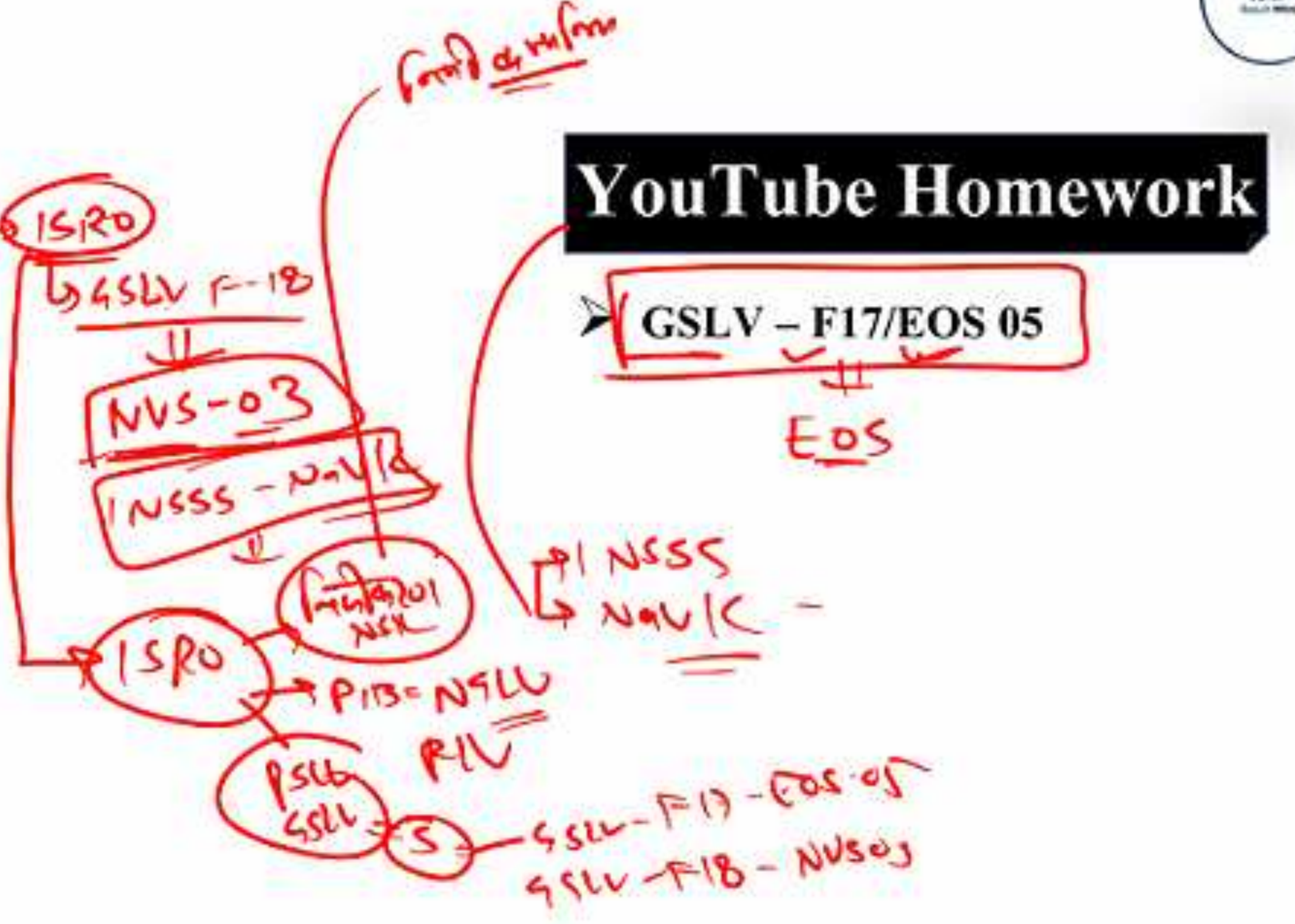
NavIC is India's independent regional navigation satellite system designed to provide accurate Position, Navigation and Timing (PNT) service to users in India as well as the region extending about 1,500 km beyond the Indian land mass, which is its primary service area.

The successful launch of the NVS-03, which will have a mission life of 12 years, is expected to restore the functioning of the NavIC constellation which has been weakened due to repeated failures of atomic clocks and the ISRO's inability to place its previous replacement satellite, NVS-02, in its intended orbit. It may be recalled that earlier this year on March 13, the last functioning atomic clock aboard IRNSS-1F had stopped working.

Friday night's launch is only the third mission to be launched by the ISRO in 2026 after the PSLV-C62 mission carrying the EOS-N1 earth observation satellite on January 12, 2026 and the EOS-05 aboard the GSLV-F17 on September 4. While the PSLV-C62 mission was a failure, the GSLV-F17 mission was a success.



The GSLV F15 rocket carrying the NVS-03 lifts off from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota on Friday night. PTI



महत्वपूर्ण तथ्य

India made 'remarkable progress' in reducing poverty, says World Bank

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

India has over the last decade made "remarkable progress" in reducing poverty across both monetary and non-monetary dimensions, the World Bank said in a new report, adding that the country saw one of the fastest reductions in poverty in the world.

"Between 2011 and 2023, the share of the population living below the Lower Middle-Income Country line ($4.2/day) fell from 57.7% to 16.1%, lifting an estimated 496 million people out of poverty, while extreme poverty ($3.00/day) declined from 27.1% to 2.6%," the World Bank said in its October 2026 Poverty and Equity Brief for India released on Friday.

Further, it said it projected poverty to continue declining, "albeit more gradually". "On the non-monetary dimensions, as measured by the Oxford Poverty and Human Development Initiative's (OPHI) Multidimensional Poverty Index (MPI), poverty fell sharply from 38.8% in 2005-06 to 16.4% in 2019-21, with the World Bank MPI measure at 15.5% in 2022-23," the World Bank said.



Extreme poverty declined from 27.1% to 2.6%, the report said.

Wage disparities

"Wage disparities, however, remain pronounced, as median earnings among the top 10% of workers were about 13 times those of the bottom 10% in 2023," the report said. "Poverty has also become increasingly concentrated geographically," it added. "While living standards improved across most States, households in a contiguous belt stretching from Uttar Pradesh to West Bengal account for about 57% of India's poor population."

Youth unemployment

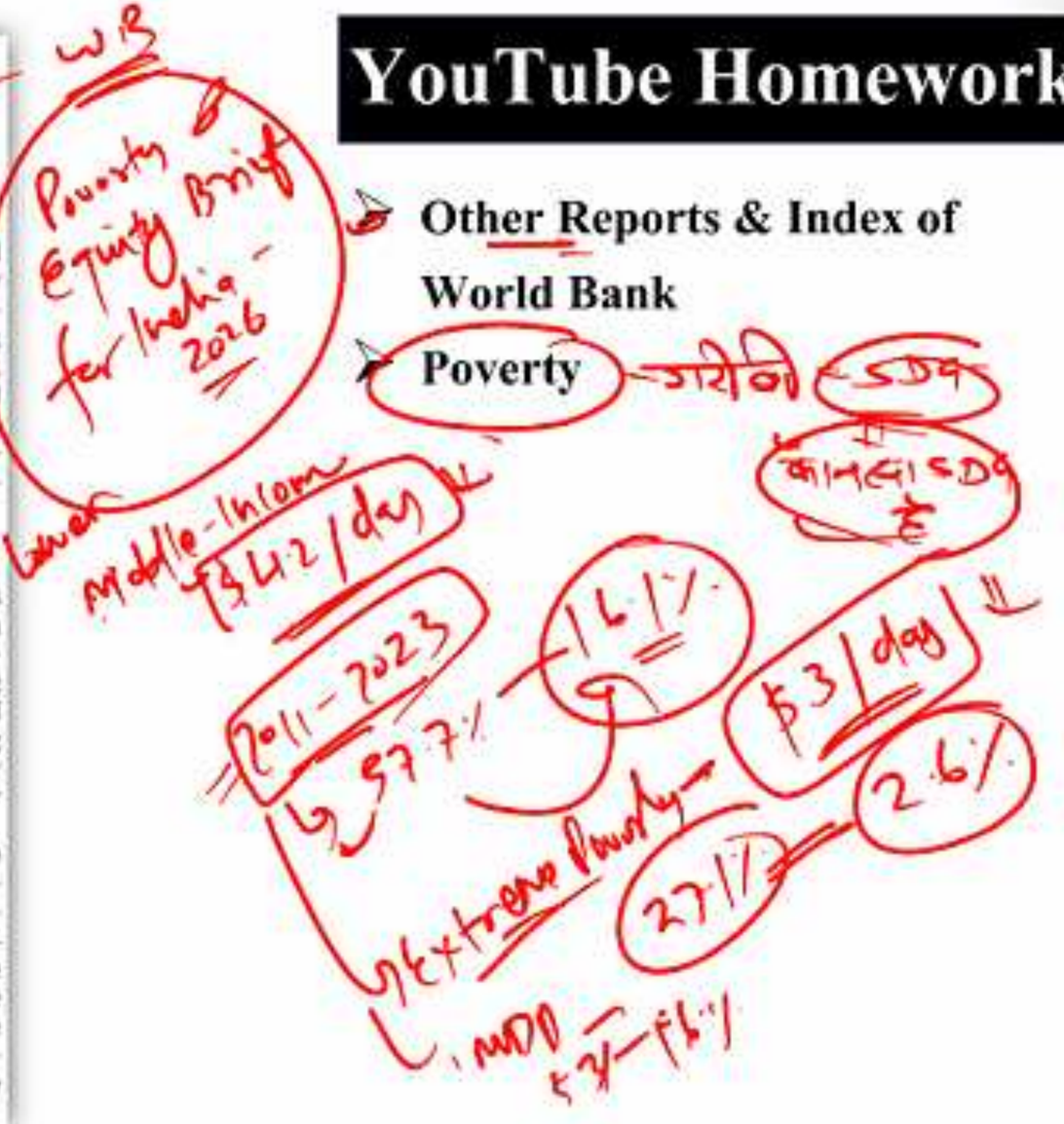
The report further noted that, between 2017 and 2023, employment increased by about 134 million people, nearly twice the growth of the working-age population, with much of the gain driven by rural women entering paid work and raising the number of earners per household.

"However, youth unemployment rose from 14.6% to 15.9% between the two quarters [Q1 FY2026 and Q1 FY2027], particularly among rural young women," the World Bank highlighted. "Moreover, real earnings remained broadly unchanged with employment growth concentrated in relatively low-productivity activities."

FM hails findings

"The World Bank identifies strong consumption growth, rising employment – especially among women – and expanded social transfers, including food subsidies, as major drivers," Finance Minister Nirmala Sitharaman said.

"Under the leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi, the Government's sustained policy efforts are yielding tangible results, strengthening the foundations for inclusive growth and greater economic opportunity," she added.



महत्वपूर्ण तथ्य

India slashed oil imports from U.S. and Russia in Sept.

Government data showed India's oil sourcing remains highly concentrated, with just Russia and the UAE accounting for 60% of oil imports, coinciding with the 'Russia Sanctions Act'

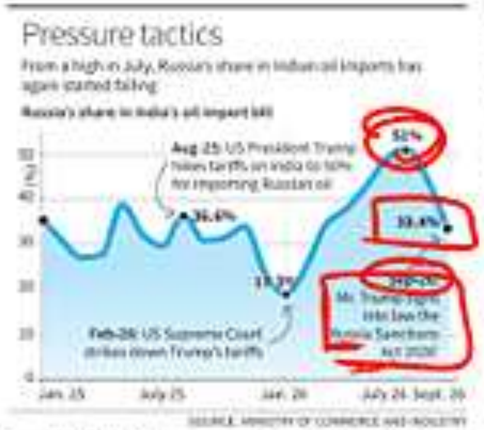
TCA Sharad Raghavan
NEW DELHI

In what looks like a direct response to the 'Russia Sanctions Act' being signed into law that month, India in September 2026 slashed its oil imports from the U.S. to zero, and drastically cut down its imports of Russian oil, the latest official data shows.

Instead, India turned to the UAE for its oil requirement, with that country's share rising to more than one-fourth of India's oil imports. As a result, India's crude oil sourcing remains highly concentrated, with just two countries – Russia and the UAE – accounting for 60% of all oil imports.

The U.S. House of Representatives on September 16 passed the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, which was then signed into law by President Donald Trump on September 18.

The law empowered the U.S. to levy tariffs of up to 500% on countries such as India and China that imported large quantities of Russian oil and gas.



The tariffs are currently in abeyance, with Mr. Trump on October 16 signing an executive order temporarily waiving the tariffs and submitting a certification to the U.S. Congress saying that the pause was in the U.S.'s national interest. The Indian government data on October oil imports will be released next month.

India imported 209.6 lakh tonnes of crude oil in September 2026, which was 9.5% higher than in August, and 4.3% higher than in September last year. However, as has been the case in the last six months or so, elevated crude oil prices have meant that India's oil import bill has swelled far faster than the growth in the actual quantity of oil being imported.

The data showed that India's oil import bill of nearly $14.3 billion in September 2026 was 16.4% higher than the bill in August, and a much more significant 33% higher than in September 2025 when oil prices were relatively more benign. Russia's share in India's oil imports has recently been broadly following the U.S.' actions regarding such imports.

Most recently, Russia's share climbed to an all-time high of around 52% in July 2026, capping off a steady climb since February when the U.S. scrapped its Russian oil-linked penal tariffs on India. This also coincided with the closure of the Strait of Hormuz due to the war in West Asia and the resultant supply constraints from that route.

However, Russia's share has fallen since then – to 44% in August, and further to 33% in September, when the 'Russia Sanctions Act' was signed into law.

In volume terms, while India increased its overall oil imports in September, it cut Russian imports by nearly 38% as compared with August.

A previous analysis by *The Hindu* shows before the penal tariffs were removed in February, India had been slashing oil imports from Russia in line with U.S pressure.



YouTube Homework

- Gas Import

महत्वपूर्ण तथ्य

केपलर (Kpler) और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत को सबसे ज़्यादा कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले **टॉप 5 देश** निम्नलिखित हैं: The Hindu +2

1. **रूस (Russia):** यह भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है, जिसकी हिस्सेदारी भारत के कुल आयात में लगभग 33% से 45% के बीच रहती है। GK Chetan Bharat Lea... +1
2. **संयुक्त अरब अमीरात (UAE):** यह दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। हाल के महीनों में (विशेषकर सितंबर 2026 में) भारत ने यूएई से तेल की खरीद काफी बढ़ा दी है। The Hindu +1
3. **इराक (Iraq):** पारंपरिक रूप से इराक भारत का शीर्ष सप्लायर रहा है और वर्तमान में भी यह भारत के मुख्य तेल स्रोतों में शामिल है।
4. **सऊदी अरब (Saudi Arabia):** खाड़ी देशों में सऊदी अरब भारत का एक और सबसे मजबूत और भरोसेमंद तेल भागीदार है। Exporters Worlds +1
5. **वेनेज़ुएला / अमेरिका (Venezuela / USA):** वैश्विक प्रतिबंधों, टैरिफ और बाजार के उतार-चढ़ाव के कारण पांचवें स्थान पर बदलाव होता रहता है। हाल के आंकड़ों में अमेरिका से आयात घटने के बाद वेनेज़ुएला और ब्राज़ील जैसे देशों की हिस्सेदारी टॉप लिस्ट में बढ़ी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Can India and China coexist peacefully?



M.K. Narayanan

Former Director, Intelligence Bureau, a former National Security Adviser, and a former Governor of West Bengal

The state of relations between China and India today can best be described as managed coexistence. The more question is whether they can, or cannot, exist peacefully in the coming decades. This issue arises because every 'patrolling deviation' is regarded as a 'face-off', endangering peace and tranquility and in the process, Sino-Indian relations. Consequently, though not at war, even managed coexistence is proving problematic. No obvious reasons exist for the two ancient civilisations to be in conflict, notwithstanding certain border disagreements.

The 1962 Sino-Indian conflict, it might be argued, was an outcome of Mao's 'hubris' in the wake of his disastrous 'Great Leap Forward', though historians also adduce several other reasons for it. Ever since the conflict, the border in the Ladakh region has remained a serious bone of contention between the two countries. For India, Mao's perfidy after years of 'Hindi Chini Bhai Bhai' meant that China could not be trusted, and the loss of territory in both Ladakh and Arunachal Pradesh became a permanent sore. However, it still does not wholly explain why feelings remain as embittered to this day.

Commentators today are prone to highlight the impact of the 2020 Galwan Valley clash between Chinese and Indian patrols (which resulted in the loss of 20 Indian soldiers) for the continuing tensions between the two countries. But the distance that exists between the two civilisations cannot be quite explained by this singular event. The time has, perhaps, come to demystify the reasons for this so that India and China can take their appointed place in the comity of nations.

An ancient divide?

Ladakh's improperly delineated terrain is often brought up as one major reason that is preventing a solution between the two nations. Similar reasons are attributed by so-called experts to explain tensions in the Arunachal Pradesh sector, where the true villain, perhaps, is as much the McMahon Line, as are the Chinese, for leaving behind an improperly demarcated border.

Recent history is replete with the many steps taken by the two countries during periods of thaw. However, nothing quite approximates to the one initiated by Prime Minister Rajiv Gandhi who, in 1988, took the initiative to visit China and meet up with leaders such as Deng Xiaoping, achieving a new watershed in relations between India and China. This has, unfortunately, been subsequently frittered away by leaders on both sides, but remains a beacon of light to this day, on how to offset tensions and improve state to state relations. The spin-off from the discussions enabled the border question to be discussed separately, often sidestepping bureaucratic hurdles and so-called military confidence building measures.

Ever since there have been many 'way stations' in the conflict between the two countries. Many of the current initiatives are, however, beginning to look like a 'zero sum game'. No doubt, extraneous aspects such as the U.S.-sponsored QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) initiative have also contributed to the perseverance of the stalemate. Moreover, Chinese strategists, who often tend to be obtuse in their thinking, believe that India's involvement in U.S. plans are a ploy to contain China. As a result, they see no reason to take steps to improve relations with India.

The most question, though, is whether India has reasons to fear China. Notwithstanding the much touted remarks of Canadian Prime Minister, Mark Carney, "that the old rules-based order is dead and that new coalitions of the willing need to be constituted to protect the interests of many countries", it would be egregious to think that this applies to India-China relations. While India and China need to sort out many issues, it would be a mistake for India to look upon China as a threat to its very existence, even though China might well visualise India, in course of time, as a challenge to its pre-eminence in certain fields. Instead of pursuing a negative trajectory, it would serve the phrase recently popularised following discussions between Chinese President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump that "building a constructive relationship of strategic stability" applies as much to Sino-Indian relations as to Sino-U.S. relations. Nevertheless, India would do well to contend with the reality — as the Economist mentioned — that "even as China produces more research about India, it seems to understand it less".

While India and China need to sort out many issues, it would be a mistake for India to look upon China as a threat to its very existence

Another aspect is, how well does India — or for that matter the rest of the world — understand the true extent of China's military strength, and its ability to win wars of the present and those of the future. India is by no means an ally of China, but it is far fetched to believe that India is its real opponent, one with whom a conflict is inevitable or imminent. Any conflict will, India would set China back several years, and derail its 2049 target of becoming supreme once in the world. India, for its part, also has no inclination to embark on a conflict with China. This, therefore, should clearly rule out direct conflict as a means to settle disputes between them. Messages would, however, have to go out to the military and border guards of both countries to ensure that instances such as the one that took place in the Galwan Valley in 2020 do not recur. In any event, neither country enjoys an edge in the disputed areas in the high Himalayas, and avoidance of inadvertent action is, hence, essential.

Understanding China is essential

It is also essential to dispel the myth of China's military edge which is often flagged by political entities and military experts. The People's Liberation Army (PLA) and the People's Liberation Army Navy (PLAN), more so the latter, have made major advances to fight future wars, but are not yet world-class. The very fact that China has refrained from embarking on a war to reclaim Taiwan also indicates the degree of realism that pervades the Chinese military. China's accretion of long range missiles and submarines, and related surveillance systems, as also its impressive amphibious ability notwithstanding, India is more than a match for China's capabilities in the high Himalayas. It is a myth perpetuated by interest groups that the threat posed by China to India is a grave one.

One does need to read China right, and avoid any thing that might bring forth a response that India had not intended. It is important, hence, to better understand China's intentions. It would also be a gross mistake to regard China as ready to test India's strength to degrade its position in the world. China knows when to bend, as was seen when under President Hu Jintao in 2005, China signed an Agreement with India to foster a long-term constructive and cooperative partnership. Article I of this Agreement stated that neither side shall use or threaten to use force against the other; and Article VII observed that in reaching a boundary settlement, the two sides shall "safeguard the due interests of their settled populations in the border areas".

It needs to be kept in mind that China's national identity is not as cohesive as one is led to think. Understanding the frailties of the 'Qing Dynasty' and the elasticity of the Dynasty's boundaries are a key primer for all nations that have to deal with China, all the more so for India. Misreading China would cost India dearly, for there is nothing in the history of the two that suggests that they have to be permanently at war. India can, today, coexist peacefully with China, and China with India.

महत्वपूर्ण तथ्य

"Can India and China coexist peacefully?"

- **भारत-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति:** वर्तमान संबंधों को 'प्रबंधित सह-अस्तित्व' (managed coexistence) कहा जा सकता है। मुख्य सवाल यह है कि क्या दोनों प्राचीन सभ्यताएं अगले कुछ दशकों में शांति से रह सकती हैं?
- **ऐतिहासिक अविश्वास और सीमा विवाद:** 1962 के युद्ध, 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के बाद चीन के धोखे, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद के कारण आज भी दोनों देशों के बीच कड़वाहट बनी हुई है। 2020 की गलवान घाटी की झड़प ने तनाव को और बढ़ाया है, लेकिन दोनों सभ्यताओं के बीच की दूरी को केवल इस एक घटना से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।
- **भू-राजनीतिक और बाहरी कारक:** भारत द्वारा अमेरिका समर्थित QUAD (क्वाड) में शामिल होने को चीनी रणनीतिकार भारत की ओर से चीन को घेरने की चाल मानते हैं।
- **चीन की सैन्य ताकत का यथार्थ:** चीन की सैन्य क्षमता (PLA और PLAN) बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत हिमालयी क्षेत्रों में चीन से मुकाबला नहीं कर सकता। भारत उच्च हिमालय में चीन की ताकत को टक्कर देने में पूरी तरह सक्षम है।

आगे की राह और निष्कर्ष:

- भारत के लिए यह भूल होगी कि वह चीन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा माने।
- दोनों देशों को सीधे संघर्ष के बजाय कूटनीति, आपसी बातचीत और सैन्य विश्वास बढ़ाने के उपायों (Confidence Building Measures) पर जोर देना चाहिए ताकि गलवान जैसी घटनाएं दोबारा न हों।
- इतिहास में ऐसे समझौते भी रहे हैं (जैसे 2005 का समझौता जिसमें बल का प्रयोग न करने पर सहमति बनी थी)। अंततः, भारत और चीन आज भी शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व के साथ रह सकते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

How AI is transforming U.S. military industrial complex



Shashank Ranjan

Indian Army veteran (Colonel), currently teaching at O.P. Jindal Global University, Sonipat, Haryana

The core of the U.S. Military Industrial Complex (MIC) is shifting from traditional hardware manufacturers to algorithm and AI companies which will lead to an obvious fallout across the global defence industrial base. Three interlocking attributes to this shift are the inversion of war economics, the restructuring of procurement and capital logic, and the "software-defined" transformation of the military technology stack. This shift was formally sanctified on September 29, 2026, when U.S. President Donald Trump convened the CEOs of the world's most powerful AI companies to sign the White House Accord on Super Intelligence – a voluntary framework that symbolically integrated AI firms into the national security architecture.

The military implications of this Accord are unmissable. Moreover, substantive developments had already occurred months earlier in the military domain. In May 2026, the U.S. Department of War announced agreements with eight AI companies – SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services, and Oracle – to deploy their capabilities on classified networks at impact levels 6 and 7, the highest classification tiers for sensitive military operations.

Drivers of the shift

The traditional MIC has operated on a 'few but exquisite' logic', which is that multi-billion dollar platforms will ensure deterrence from other parties as they would be technologically overpowered. This logic has, however, been exposed as economically unsustainable and fragile. In recent conflicts, the U.S. and allied defences were compelled to expend expensive interceptors against cheap drones.

The Pentagon's response has been a dramatic funding shift. The Defence Autonomous Warfare Group (DAWG), which absorbed the stalled Biden-era Replicator Initiative (rapidly fielding thousands of low-cost, uncrewed autonomous systems across multiple domains) saw its budget projections jump from $225.9 million in FY26 to $54.6 billion in the upcoming FY27.

If war economics created demand, capital markets provided the supply-side solution. The traditional MIC relied on "cost-plus" contracts, incentivising risk aversion and prolonged timelines. The new players or the neo-primes, which are software companies such as Palantir, SpaceX, Anduril etc., employ fixed-price contracts, absorbing upfront costs and trading on-time delivery for higher margins. The combined enterprise value of the neo-primes exceeds the value of the 'Big Three' companies (Lockheed Martin, RTX, and Northrop Grumman) by three times, despite revenues nearly eight times smaller.

The explanation lies in procurement reform. In March 2026, the Army awarded Anduril a 10-year, $20 billion enterprise contract that consolidated more than 120 separate procurement actions into one acquisition component. The U.S. Army has signed 14 such enterprise contracts in eight months, replacing 118 individual contracts – an 88% reduction in contract volume. Programs that took seven years to award now move in months. Palantir's Maven Smart System was formally designated an 'official program' with locked-in long-term funding, which was the first time a Silicon Valley company has been directly embedded into the defence budgetary skeleton.

The May 2026 agreements by Pentagon with AI companies laid out the functional layers of the algorithmic military stack. The algorithm and the layered-model constitute the brain which include OpenAI (multilingual intelligence analysis), Google (satellite imagery target recognition), and Reflection AI (autonomous combat agents). The compute layer is provided by Nvidia's military-grade GPU clusters. The cloud services layer is built by Microsoft, Amazon, and Oracle. The communications layer is by SpaceX's Starlink and Starshield while Palantir and Anduril serve as strategic hubs and frontline execution terminals (edge AI, drone swarms, counter-drone systems). The core thesis of "software-defined warfare" is that codes and not platforms have become the decisive differentiator. A warship's systems can become smarter overnight through a single download, and drones can switch from reconnaissance to electronic attack by loading a different software.

Traditional contractors however, have not disappeared. Lockheed, RTX, and Northrop still receive the vast majority of defence budget dollars and spend far more on lobbying. However, the symbolic indicators have reversed: capital market valuations now reflect investors' judgment about the future shape of the MIC.

Concern about vulnerabilities

In breaking with traditional contractors, the Pentagon may create new dependencies – Palantir's battlefield systems and SpaceX's launch capabilities could become the new single points of failure. More fundamentally, the speed of commercial AI iteration creates a verification gap. As AI companies deploy at commercial velocity, the Pentagon's test and evaluation system, designed around static hardware, may not be enough. Certain programmes are still difficult to be validated. The vulnerability can be serious in the eventuality of unvalidated software-defined weapons failing due to a cyberattack.

The core of the MIC has shifted from the factory to the server due to the arithmetic of cost-imposition, the venture-velocity logic of capital, and the architectural revolution of software-defined warfare Victory in future wars may now depend on algorithms, data, and code.

महत्वपूर्ण तथ्य

"How AI is transforming U.S. military industrial complex"

- **सैन्य-औद्योगिक परिसर (MIC) में बदलाव:** अमेरिकी सैन्य-औद्योगिक परिसर पारंपरिक हार्डवेयर निर्माताओं से हटकर एल्गोरिदम और AI कंपनियों की ओर बढ़ रहा है।
- **व्हाइट हाउस एकॉर्ड और नीतिगत बदलाव:** 29 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'व्हाइट हाउस एकॉर्ड ऑन सुपर इंटेलिजेंस' पर हस्ताक्षर किए, जिसने AI फर्मों को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया।
- **सॉफ्टवेयर-डिफाइंड युद्ध (Software-Defined Warfare):** अब युद्ध के तरीके बदल रहे हैं जहाँ भारी-भरकम प्लेटफॉर्म्स की जगह कोड और सॉफ्टवेयर सबसे महत्वपूर्ण हो गए हैं; एक सिंगल डाउनलोड से युद्धपोत और ड्रोन अधिक स्मार्ट बन सकते हैं।
- **नई टेक कंपनियों (Neo-Primes) का उभार:** Palantir, SpaceX, Anduril जैसी नई कंपनियाँ फिक्स्ड-प्राइस अनुबंधों और तेज डिलीवरी के जरिए आगे बढ़ रही हैं, जिनका बाजार मूल्य अब पुरानी रक्षा कंपनियों (जैसे Lockheed, RTX) से भी अधिक हो गया है।
- **कमजोरियाँ और चिंताएँ:** पेंटागन द्वारा पारंपरिक ठेकेदारों को छोड़कर नई टेक कंपनियों पर निर्भर होने से नए खतरे पैदा हो सकते हैं (जैसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर या साइबर हमले का जोखिम), क्योंकि सॉफ्टवेयर आधारित हथियार प्रणालियों का परीक्षण अभी भी एक चुनौती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

'Israel committed war crimes, genocide even after Gaza truce'

Israeli military operations and settler violence in West Bank were part of coordinated attack against Palestinians aimed at entrenching settlements, annexing territory and displacing its population, says UN commission led by Justice Muralidhar

Stanly Johny

Israeli forces have continued to commit war crimes, crimes against humanity and genocide in the occupied Palestinian territory even after the ceasefire agreement in Gaza, a UN commission of inquiry has said.

In a report presented to the UN General Assembly, the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory said Israeli military operations and settler violence in the West Bank were part of a coordinated attack against Palestinians, aimed at entrenching settlements, annexing Palestinian territory and displacing its population.



A cruel occupation: Palestinian children stand amid the rubble after a building was hit overnight by an Israeli strike in Gaza on Friday. AFP

The commission, Chaired by Justice Srinivasan Muralidhar, said more than 75,000 Palestinians, including at least 21,500 children and 11,000 women, had been killed across the occupied Palestinian territory since October 7, 2023, the day Hamas carried out an attack in Israel, killing 1,200 people. It said the death toll had continued to rise despite the October 2025 ceasefire.

"Failure to act now is particularly egregious against the backdrop of the staggering death toll which has continued to rise since the so-called ceasefire," said Justice Muralidhar in his statement at the UN on October 26.

Territorial control

In Gaza, Israeli forces have continued expanding their territorial control, resulting in the killing and injuring of Palestinian civilians, including children, who approach or cross the Yellow Line, which separates Israel-military controlled Gaza from the Palestine-ruled parts of the enclave, he said.

The findings contradicted claim by the Board of Peace in its May report to the Security Council that the ceasefire had largely held and brought enormous relief to civilians.

The Justice said the situation in the West Bank had deteriorated significantly since October 2023.

The commission concluded that Israel had committed crimes against humanity, including extermination, torture, rape and other forms of sexual violence. It also accused Israeli authorities of persecution through discriminatory rules of engagement that applied exclusively to Palestinians.

The report traced the roots of Israeli violence to policies dating back to the 1947-48 war, arguing that Israel had sought to maximise territorial control while minimising the Palestinian population through displacement and the use of lethal force.

The report also documents the expansion of Israeli military operations in the West Bank, including air strikes and the destruction of refugee camps.

It says military operations since January 2025 have resulted in the largest displacement of Palestinians in the West Bank since 1967, with 34,076 people still displaced as of August 2026.

Justice Muralidhar, addressing the gathering via a video link, also criticised Palestinian security forces for using unnecessary or disproportionate force against Palestinians in the West Bank.

It said the Palestinian Authority had failed to conduct effective and impartial investigations into killings and provide remedies to victims.

Calling on Israel to end its occupation and comply with the International Court of Justice's (ICJ) July 2024 advisory opinion, Justice Muralidhar urged Member states to stop providing assistance that could sustain the occupation and settlements. He also called on states to use all available means to prevent and punish genocide and support the International Criminal Court (ICC).

He said he addressed the committee through a video statement because he had not received a U.S. visa despite efforts to meet the requirements.

Israel's Permanent Representative to the UN Danny Danon, in his response, rejected the commission's findings, describing the report as "works of historical fiction".

He accused the commission of "seeking to challenge Israel's legitimacy", and said it had taken "terrorist talking points and turned them into an official UN document."

Evidence gathering

Justice Muralidhar, in his concluding remarks, defended the commission's work, saying its findings were based on "painstakingly gathered evidence".

"The evidence gathering protocols [of the commission] were aligned with those of the International Court of Justice and the International Criminal Court. The commission followed the highest professional standards and reached conclusions only after satisfying itself of the evidence," he said.

He added that the commission was ready to share its evidence with any adjudicatory body seeking to investigate the allegations.

"Israel has refused to cooperate with the commission and has denied it access to the occupied Palestinian territory since its work began."

महत्वपूर्ण तथ्य

UPSC / UP PCS / 13 BPSC

Rubio hosts G20 Ministers, including Russia's Lavrov

Agence France-Presse
ATLANTA


Marco Rubio

United States (U.S.) Secretary of State Marco Rubio on Friday told G20 counterparts including Russia's Sergei Lavrov that the world faces a decisive moment to tackle geopolitical crises, as wars in Ukraine and on Iran deepen rifts between member countries.

Already, a traditional group photo planned for Friday morning was called off shortly before the two-day meeting started, as some European officials objected to appearing alongside Mr. Lavrov, a diplomatic source told AFP.

European leaders have opted not to appear in photos with Russian delegations in earlier G20 meetings this year too, as fighting continues after Russia's 2022 invasion of Ukraine.

A U.S. official said the photo was cancelled due to the controversy and to avoid allowing "a ceremonial photo opportunity to become a diplomatic distraction."

The Foreign Ministers' gathering in Atlanta, Georgia, taking place just days before the U.S. midterm elections, also comes as global energy prices have rocketed since the U.S. war on Iran.

It sets the stage for a December G20 leaders' summit in Miami at President Donald Trump's Doral resort.

But, even as the U.S. seeks to focus on economic growth, trade imbalances and supply chain challenges – covering areas like energy and critical minerals – few breakthroughs are expected.

A diplomatic source said that instead of a final declaration, this week's meeting will likely conclude with a chair summary drafted by the U.S.

Mr. Rubio told an opening plenary Friday that the world faces a critical "moment of choosing" as it grapples with "interconnected economic and geopolitical crises."

He urged the group of 20 economies – which include China, India, Russia, Japan, Germany and France – to work together against threats like strains on global energy and food supply chains, and on freedom of navigation.

'No normality'

Russia has been shunned by most of the West after its 2022 invasion, and Mr. Lavrov himself remains under international sanctions.

German Foreign Minister Johann Wadephul told German media ahead of the Atlanta meeting that "there is no normality with Russia."

"Today, in this forum, I will once again call on Russia to finally accept Ukraine's offer of a ceasefire, starting in the Black Sea," he said.

G-20 Foreign Minister meeting
Atlanta USA

YouTube Homework

- 12th BRICS Parliamentary Forum
- 13th ASEAN Defence ministers Meeting

महत्वपूर्ण तथ्य

Thousands of students, workers protest in Italy

Agence France-Presse
ROME



Classes on streets: Students during a demonstration demanding more funding for education and better support for housing, in Rome on Friday. AFP

Thousands of students and workers took to the streets across Italy on Friday, calling for more school funding and relief from the soaring cost of living, amid a high police presence to avert possible clashes.

Friday's Italy-wide protest comes after weeks of demonstrations, led by students who have set up tent camps and occupied schools to make their demands heard, fuelled by similar movements in nearby France and Spain.

A general strike called by Italy's USB trade union attracted thousands of workers to Friday's protests, including truck drivers, taxi drivers and farmers who have rallied in recent weeks over the spike in fuel prices and to oppose rising defence spending.

Marches were held in dozens of cities in the country, including in Bologna, Genoa, Naples, and Turin – where a few minor skirmishes between protesters and riot police occurred at the start of the protest.

In Rome, university student Beatrice Chilelli told *AFP* students were "at a breaking point". "They can't afford to pay exorbitant tuition fees, and rent... which weighs heavily on parents' shoulders," said the 20-year-old, citing student housing in Rome that could reach 1,200 euros per month for one room.

"We need more houses, not bombs!" sang one group in the crowd, as a troupe of protesters gave a brief performance imitating terrified civilians in a Gaza bombing raid.

The Milan protest also began at the central train station, but then headed outside the city – far from the centre where young vandals had looted stores, destroyed property and clashed with police two weeks ago after another sanctioned cost-of-living demonstration. Police in riot gear blocked off streets, but no major clashes had been reported as of midday.

Besides students, the demonstrators at Friday's protest included teachers, workers and retired people. Many pro-Palestine flags were seen in the crowds in major cities.

Student Protest
Neo Liberalism
Right wing
France
Italy

YouTube Homework

- Neo Liberalism & Student Protest

महत्वपूर्ण तथ्य

New York moves to protect children from harmful AI chatbot interactions

NEWS ANALYSIS

Mantasha Ahmed
CHENNAI

"As a mother and grandmother, I believe kids deserve to be kids, without dangerous AI chatbots putting their safety and mental health at risk. ...Big Tech, you're on notice," New York Governor Kathy Hochul wrote on social media after signing two Bills on Wednesday, aimed at protecting children from the risks associated with artificial intelligence (AI) chatbots and internet-connected baby monitors.

The legislation prohibits AI chatbots from engaging in potentially harmful interactions with minors, including simulating romantic relationships, encouraging emotional dependency, and promoting self-harm. It also requires manufacturers of internet-connected baby monitors to introduce safeguards against unauthorised access to audio and video feeds.

The measures are part of New York's broader efforts to regulate emerging technologies amid growing concerns over children's online safety and privacy.

Growing concerns

The growing popularity of AI companions among teenagers in the United States and across the globe has raised concerns about their potential psychological and emotional impact. Unlike conventional chatbots that primarily respond to queries, AI companions are designed to sustain personalised conversations, simulate human emotions and, in some cases, establish relationships resembling friendships or romantic attachments.

According to research cited by the New York administration from *Common Sense Media*, 72% of teenagers surveyed had used AI companions at least once, while 52% reported using them at least a few times a month. The concerns surrounding such platforms have intensified following reports of teenagers developing emotional attachments to AI chatbots and receiving potentially harmful responses during conversations about mental health and self-harm.

Governor Hochul referred to the death of Adam Raine, a California teenager who died by suicide following interactions with an AI chatbot. His family has alleged that the chatbot encouraged harmful behaviour and failed to respond appropriately to signs of distress. The case has brought renewed scrutiny to the responsibility of AI companies in protecting vulnerable users, particularly minors.



New York Governor Kathy Hochul signed a Bill prohibiting firms from offering specified chatbot features to minors. FILE PHOTO

The baby monitor legislation, meanwhile, addresses cybersecurity vulnerabilities in devices that allow parents to remotely monitor their children through internet-connected cameras and microphones. The Governor's office cited reports that video feeds from more than 10 lakh internet-connected baby monitors were accessible through a website, potentially exposing private moments inside family homes to unauthorised viewers.

Provisions of the law

The legislation prohibits companies from offering specified AI chatbot features to users below the age of 18, as well as users whose adult status has not been verified. Under the law, AI chatbots cannot falsely present themselves as real people, claim to possess human emotions or simulate personal relationships with children.

The restrictions also cover responses designed to manipulate children's emotions or encourage prolonged engagement through excessive flattery and people-pleasing behaviour. Chatbots are prohibited from initiating certain emotionally probing conversations or using sensitive personal and health information disclosed during previous interactions in ways restricted by the legislation. The law further prohibits AI systems from promoting or assisting suicide, self-harm, eating disorders and substance misuse. It also bars chatbots from encouraging children to conceal information from parents or trusted adults, withdraw from social relationships or avoid seeking professional assistance. Sexually explicit interactions and child sexual abuse material are also prohibited.

Importantly, the legislation does not impose a blanket ban on minors using AI chatbots. Instead, it restricts specific features and interactions considered harmful to children. Companies are required to introduce age-verification mechanisms, offering users more than one method of establishing their age, including an option that does not depend solely on government-issued identification. Information collected for age verification must be deleted after its intended use.

The New York Attorney General has been empowered to enforce the legislation and initiate legal proceedings against companies found violating its provisions. These violations can attract civil penalties of up to $25,000 (₹23,73,637) per violation, with damages, restitution and court orders requiring companies to discontinue prohibited practices. The law also provides for the destruction of information collected unlawfully.

महत्वपूर्ण तथ्य

Uniform Civil Code in U.P. if BJP voted to power again: Shah

Mayank Kumar
LUCKNOW

Union Home Minister Amit Shah on Friday said a Uniform Civil Code (UCC) will be implemented in Uttar Pradesh if the Bharatiya Janata Party (BJP) won the 2027 Assembly election.

Urging party workers to work towards winning the polls, he said, "The Uniform Civil Code has been implemented in several States. Uttar Pradesh will be the next. Make a Bharatiya Janata Party government, and we will implement the UCC here."

Mr. Shah, who was addressing the BJP's State executive meeting here, said the BJP will get a "massive majority" in the State.

"The BJP government in Uttar Pradesh is as firmly rooted as Angad's foot, and no one can dislodge it. Our party is once again going to form the government in U.P. with a massive majority," he said.

Mr. Shah also challenged the Leader of the Opposition, Rahul Gandhi, and the Samajwadi Party (SP) chief, Akhilesh Yadav, to a debate on the special intensive revision (SIR) but said they just want to "create a ruckus".

"I challenge both [of] you (Mr. Gandhi) and Akhilesh Yadav right here and now: the BJP is fully prepared to discuss this (SIR row) in Parliament. We have nothing to hide. Let us convene a special session of Parliament, but they have no intention of speaking there. They refuse to let Parliament function. Instead, they just create a ruckus."



Amit Shah, centre, and Yogi Adityanath, left, during the U.P. BJP working committee meeting in Lucknow on Friday. PTI

Praise for Adityanath

Hailing Chief Minister Yogi Adityanath, Mr. Shah said, "I want to praise Chief Minister Yogi Adityanath. Under his leadership, the government has provided strict governance and freed Uttar Pradesh from the mafia."

Hitting out at the SP, Mr. Shah wondered how the party could talk about forming a government after opening fire on Ram devotees. "Today is October 30. This date holds importance in Uttar Pradesh and in the entire nation. On this day in 1990, then Uttar Pradesh Chief Minister Mulayam Singh Yadav ordered firing on Ram devotees. I would like to ask the Samajwadi Party today, how can you talk about forming a government after opening fire on Ram devotees? We are the party that worked towards the construction of the Ram Temple," he said.

-UP LA -2027
UP - 3 पर - BJP
UCC

YouTube Homework

UCC
कितने राज्यों में लागू है

महत्वपूर्ण तथ्य

रक्षा मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस तरकश मॉरीशस के पोर्ट लुईस बंदरगाह पहुंचा

प्रविष्टि तिथि: 30 OCT 2026 7:54PM by PIB Delhi

भारतीय नौसेना का पोत आईएनएस तरकश दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नियमित तैनाती के तहत 30 अक्टूबर, 2026 को मॉरीशस के पोर्ट लुईस पहुंच गया है। यह यात्रा भारत और मॉरीशस के बीच सशक्त होती हुई समुद्री साझेदारी का प्रतीक है। इससे पेशेवर संवाद, संयुक्त गतिविधियों तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच नौसैन्य सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने का अवसर मिलेगा।

बंदरगाह पर ठहराव के दौरान आईएनएस तरकश का चालक दल मॉरीशस तटरक्षक बल के कर्मियों के साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेगा। इनमें संयुक्त प्रशिक्षण भी शामिल है, जिसका उद्देश्य परिचालन अनुभव एवं सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को साझा करना, दोनों बलों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना और समन्वय को मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान-प्रदान और सामुदायिक संपर्क से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इनके माध्यम से दोनों देशों के कर्मियों को एक-दूसरे से बातचीत करने तथा आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने का अवसर मिलेगा।

आईएनएस तरकश 2 नवंबर, 2026 को मॉरीशस के 1924 अप्रवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेगा। यह वार्षिक आयोजन 2 नवंबर, 1834 को पोर्ट लुईस स्थित अप्रवासी घाट पर भारत से आए अनुबंधित श्रमिकों के पहले जत्थे के आगमन की याद में मनाया जाता है। यह दिवस उन श्रमिकों की ऐतिहासिक विरासत, उनके संघर्षों और योगदान को सम्मान देने का अवसर है। आज उनके वंशज मॉरीशस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं और उन्होंने देश के सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कार्यक्रमों में आईएनएस तरकश की भागीदारी भारत और मॉरीशस के बीच गहरे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है।

YouTube Homework

INS इनाडि महेन्द्र

महत्वपूर्ण तथ्य

भारत सरकार ने 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' का गठन किया

श्री सुरेश एन. पटेल, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, समिति के अध्यक्ष होंगे; तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ — श्री तिरीष चंद्र मुर्मू (उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक), श्रीमती पद्मजा चुंदरू (पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बैंक) और श्री एन. एस. विश्वनाथन (पूर्व उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक) समिति के सदस्य होंगे

'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति' की घोषणा केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में की थी

समिति भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करेगी और इसे विकसित भारत, 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप बनाने हेतु सुधारों की सिफारिश करेगी

प्रेस विज्ञप्ति: 30 OCT 2026 7:28PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करने और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से समावेशी तथा विकसित भारत, 2047 के लिए मज़बूत बनाने हेतु आवश्यक संरचनात्मक, संस्थागत, नियामक एवं विधायी सुधारों की सिफारिश करने के लिए 'विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति' का गठन किया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2026-27 के दौरान इस समिति के गठन की घोषणा की थी।

श्री सुरेश एन. पटेल, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त, तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ—श्री तिरीष चंद्र मुर्मू (उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक), श्रीमती पद्मजा चुंदरू (पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडियन बैंक) और श्री एन. एस. विश्वनाथन (पूर्व उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक) समिति के सदस्य होंगे। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव (बैंकिंग) समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति का कार्यकाल छह महीने होगा।

समिति के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference)

- वर्तमान बैंकिंग प्रथाओं और प्रुडेंशियल मानदंडों का आकलन करना, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना, उन्हें भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए उपयुक्त रूप से अपनाना, तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बैंक बनाने के लिए रोडमैप प्रदान करना।
- बैंकों के लिए मौजूदा नियामक और कानूनी ढांचे की समीक्षा करना, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं, तथा इनमें दक्षता लाने और विकसित भारत के लिए बैंकिंग में कारोबार करने में सुविधा प्रदान करने हेतु सुधारों का सुझाव देना।
- बैंकों की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करना, जिसमें विकास वित्तीय संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल हैं, तथा साख वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) को समर्थन देने के लिए वित्तपोषण स्रोतों और सक्षम तंत्र पर सिफारिशें करना।
- व्यवसायों के लिए पूंजी की लागत में अंतरों की जांच करना, तथा सतत विकास के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत विकल्प सुझाना।
- बैंकिंग संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल नवाचार के लिए रोडमैप तैयार करना, साथ ही साइबर जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा उपाय प्रदान करना। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र के लिए भविष्य के लिए तैयार कार्यबल सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभा अधिग्रहण और क्षमता निर्माण की रणनीति सुझाना।
- प्राथमिक क्षेत्र ऋण (प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग) ढांचे और लीड बैंक योजना की समीक्षा करना, ताकि बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं और वित्तीय समावेशन लक्ष्यों के अनुरूप समायोजी, संतुलित तथा डेटा-आधारित साख वितरण को बढ़ावा देने में उनकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और समन्वय का आकलन किया जा सके।
- भारत सरकार द्वारा समिति को सौंपे गए किसी अन्य विषय पर सिफारिशें करना।

महत्वपूर्ण तथ्य

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

युवाओं में चुनावी जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें' के 46 कार्यक्रम आयोजित किए गए

30 अक्टूबर को देशभर में आयोजित कार्यक्रमों में 6,688 युवाओं ने भाग लिया; 5 नवंबर तक 500 विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों को इस राष्ट्रव्यापी अभियान के दायरे में लाने का लक्ष्य है

प्रविष्टि तिथि: 30 OCT 2026 7:51PM by PIB Delhi

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग के अंतर्गत मेरा युवा भारत (माय भारत) द्वारा आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित 'विकसित भारत युवा संवाद: अपना वोट जानें' के 46 कार्यक्रमों में कुल 6,688 युवाओं ने भाग लिया। 26 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक चलाए जा रहे इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य देशभर के 500 विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच बनाना है।

इस पहल का उद्देश्य युवाओं, विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में चुनावी जागरूकता बढ़ाना और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सोच-समझकर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के अधिकारों, चुनावी प्रक्रियाओं और नागरिक जिम्मेदारियों से परिचित कराना है। साथ ही, उन्हें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, युवा आइकॉन और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के साथ लोकतांत्रिक भागीदारी तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका पर संवाद करने का अवसर प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण तथ्य

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

व्यावसायिक जोखिमों से गरिमापूर्ण कार्य की ओर

नमस्ते योजना किस तरह स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षा को बेहतर बना रहा है

प्रेस विज्ञप्ति तिथि: 30 OCT 2026 7:46PM by PIB Delhi

रमेश कुमार(बदला हुआ नाम) के लिए, नमस्ते योजना के तहत प्रदान की गई सहायता केवल उपकरणों और प्रशिक्षण की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वच्छता कर्मियों को पहचान, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक गरिमा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और अधिक सुरक्षित कार्य परिस्थितियों ने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया है तथा उन्हें अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ने में मदद की है।

37 वर्षीय रमेश कुमार, जो अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और सेप्टिक टैंकों से मल कीचड़ निकालने के कार्य में सहायक के रूप में कार्यरत हैं, ने स्वच्छता संबंधी कार्यों से जुड़ी व्यावसायिक चुनौतियों का सामना किया है।

खतरनाक जमीनी परिस्थितियों का लगातार सामना करना, सुरक्षा उपकरणों की कमी और कल्याणकारी सुविधाओं तक सीमित पहुंच ने उनके पेशे को बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया था। काम से जुड़े इन खतरों के अलावा, उन्हें सामाजिक कलंक, कम वेतन और आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा, जबकि उन पर अपने वृद्ध माता-पिता सहित परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी थी।

इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, उनकी आकांक्षा थी कि वे सम्मानपूर्वक अपना काम जारी रखें, अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करें तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाएं। हालांकि, उचित सुरक्षा उपकरणों का अभाव, कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी उपायों के प्रति सीमित जागरूकता और अपर्याप्त स्वास्थ्य सहायता उनके मार्ग में प्रमुख बाधाएं बनी हुई थीं।

वर्ष 2025-26 के दौरान नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम(नमस्ते) योजना के माध्यम से उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव आया। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। इस योजना के तहत रमेश को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण(पीपीई) किट, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड तथा कौशल एवं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

Home Assignment

- National Deworming Day
- PM-MANDHAN Scheme

Thanks For Watching

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Subscribe Now

Stay Connected



